भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के आधार जून, 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 1,58,226 थी जो कुल लघु उद्योग के उधार खातों का 7.8 प्रतिशत है । इन एककों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी गयी निवेश राशि 1480.95 करोड़ रुपये थी ।

(घ) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने तथा रुग्ण इकाइयों को पुनः स्थापित करने हेतु अनेक अभ्युपाय किये गये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1987 में वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं जो प्रारंभिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने, रुग्ण लघु इकाइयों का पता लगाने, जीव्यता के मानदंड, जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के मामलों में पुनः स्थापना पैकेज का कार्यान्वयन करने के लिये बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली राहतों और रियायतों के बारे में है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मई, 1986 में स्थापित लघु उद्योग विकास निधि (एस०आई०डी०एफ०) से उन रुग्ण जीव्यक्षम लघु इकाइयों की पुनः स्थापना के लिये भी सहायता मिलती है जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य लघु उद्योग विकास निगमों से वित्तीय सहायता मिली हुई है । लघु क्षेत्र में जीव्यता की संभावना वाली इकाइयों को अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी फंड से प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के मामूली सेवा प्रभार पर उन एककों जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रु० से अधिक नहीं है, को 75,000 रु० तक की दीर्घकालिक इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय मदद भी उपलब्ध है। भारत सरकार ने रुग्ण लघु औद्योगिक इकायों का पुनरुत्थान करने के लिये सीमांत धन योजना का उदारीकरण किया है और इस योजना के अधीन सहायता की मात्रा की प्रति इकाई 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है ।

ग्रामीण लघु उद्योगों का उत्पादन

2058. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे ग्रामीण लघु उद्योगों द्वारा देश के उत्पादन में पर्याप्त योगदान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग क्षेत्र में पिछड़े वित्तीय वर्ष 1987-88 में कुल कितने रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ और इसमें से कितने रुपये मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ग) इस उद्योग क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और उसमें कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्य योजना बनायी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ग्रामीण लघु उद्योगों संबंधी जानकारी/आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (1985-90) के अनुसार उत्पादनकारी क्षेत्र द्वारा किये गये मूल्य वर्धन उत्पादन के मूल्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों का हिस्सा 50% होता है

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किये गये उत्पादन के मूल्य निर्यातों और रोजगार के अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट 148, अनुबंध संख्या 90]। पूंजी निवेश के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) ग्रामीण और और लघु उद्योगों के संवर्धनार्थ अनेक अभ्युपाय किये गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं- संस्थानात्मक सहायता का प्रावधान तथा प्रोत्साहन और रियायतें देना जैसे राजकोषीय और वित्तीय लाभ सामान्य सुविधा सेवाएं तथा प्रशिक्षण, विपणन सहायता कच्चे माल हेतु सहायता, डिजाइन और तकनीकी, परामर्श और जांच कार्य संबंधी सुविधाएं।

योजना व्यय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2059. श्री राम चरित्र राय :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उद्योगों का योजना व्यय स्वीकृत व्यय से बढ़ जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अतिरिक्त व्यय के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस अतिरिक्त व्यय का वर्गीकरण किया है यदि हां, तो प्रशासनिक मुद्दों उत्पादन लागत और परिवहन और रख-रखाव आदि जैसी विभिन्न मदों पर होने वाले संभावित व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना 31-3-1990 को समाप्त होगी, इसलिये इतनी जल्दी यह बताना कठिन है कि क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजनागत व्यय स्वीकृत परिव्यय से अधिक होगा।

बिजली की वार्षिक आवश्यकता और उत्पादन

2060. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक साल में बिजली की कुल संभावित खपत का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में देश में बिजली की कुल कितनी आवश्यकता होगी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये बिजली उत्पादन की औसत वार्षिक दर क्या रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और चालू वर्ष की प्रथम छमाही में कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा चुका है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, ऊर्जा की अनुमानित मांग 229000 मिलियन यूनिट होगी जब कि इसकी उपलब्धता 209070 मिलियन यूनिट होगी।

(ग) जी, हां।